involved in stock shortages, appropriate disciplinary action is also taken.

(e) As stated in reply to part (a) to (c) above.

Consumer Organisations in the Country

5049. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government's attention hos been drawn to a write up in the "Pioneer" dated the 25th March, 1995 to the effect that consumer movement is still at its infancy in the country;

(b) the number and names of consumer organisations in the country at present;

(c) their success in spreading general consumer awareness in the country. and

(d) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) At present, more than 500 voluntary consumer organisations are working in the country. The Directory of the name and addresses of such voluntary consumer organisotions is available in the Parliament Library.

(c) As a result of various measures like Consumer Awareness Programme on Radio, TV and News papers, distribution of printed material, seminars, essay competition, etc, undertaken by the Government and non-Governmental agencies, a strong consumer movement is slowly, cut firmly emerging on the Indian scene.

(d) Government welcomes the formation of voluntary consumer organisations in the rurol areas too.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

5050. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को लकड़ी का उपयोग करना पड़ता है और इसके कारण वनों की कटाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की मांग को पूर्ण रूप से पूरी करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटासिंह) (क) से (ग) मिट्टी का तेल एक कम मात्रा में उपलब्ध उत्पाद है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इसका वितरण राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। 1994–95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मिट्टी के तेल की लगभग 88 लाख मीटरी टन मात्रा आवंटित की गई थी। 1994–95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विगत वर्ष की तुलना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु मिट्टी के तेल के कुल आवंटन में 3 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी है। 1995–96 में भी विगत वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई है। देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता में और सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने मिट्टी के तेल के आयात को अमार्गीकृत कर दिया है, जिसके तहत कोई भी निजी पार्टी मिट्टी का तेल आयात कर सकती है तथा बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेच सकती है।